Content is available at: CRDEEP Journals
Journal homepage: http://www.crdeepjournal.org/category/journals/ijbas/

International Journal of Basic and Applied Sciences
(ISSN: 2277-1921) (Scientific Journal Impact Factor: 6.188)

UGC Approved-A Peer Reviewed Quarterly Journal

Full Length Research Paper

सरकारी और निजी विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता: उच्च माध्यमिक स्तर पर एक तुलनात्मक दृष्टि

रंजु कुमारी[1] व डॉ० दीपक कुमार
शिक्षा विभाग, साई नाथ विश्वविद्यालय राँची, झारखण्ड

ARTICLE DETAILS

Corresponding Author:
रंजु कुमारी

Key words:
निजी, उच्च, शैक्षिक गुणवत्ता, सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक परिदृश्य

ABSTRACT

उत्तराखंड के विविध स्थलाकृतिक और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित शैक्षिक परिदृश्य में विशिष्ट चुनौतियाँ और अवसर सामने आते हैं। इस अध्ययन में झारखंड के सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता की तुलना की गई है, जिसमें असमानताओं के कारणों की पहचान और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। इस शोध में छात्रों के प्रदर्शन के आँकड़े, शिक्षक योग्यता, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, और हितधारकों की धारणाओं सहित संख्यात्मक और गुणात्मक अंतर्दृष्टियों का उपयोग किया गया है। परिणामों में संसाधनों, शिक्षण पद्धतियों, और सीखने के परिणामों में सरकारी और निजी संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण असमानताएँ उजागर होती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष में शैक्षिक गुणवत्ता के अंतर को कम करने और झारखंड के सभी स्कूलों में समान शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक सिफारिशें शामिल हैं ।

प्रस्तावना

झारखंड राज्य, जो अपनी भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच की यह असमानता विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस शोध का उद्देश्य इन दोनों प्रकार के विद्यालयों के बीच के अंतर को समझना और इसके निवारण के उपाय सुझाना है। स्वतत्रंता शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के कारण ही आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में स्थान रखता है। शिक्षा का केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह समाज के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। शिक्षा का केवल व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है।

शिक्षा के माध्यम से ही समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर किया जा सकता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों ने इसे और भी मजबूत और प्रभावी बनाया है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानप्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। शिक्षा से ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।स्वतत्रंता के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों के कारण आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन निरंतर प्रयासों के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है और भारत को शिक्षा क्षेत्र में और अधिक प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है।

अनुसंधान विधियाँ

शोध में झारखंड के विभिन्न जिलों से सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आकड़े एकत्रित किए गए। इन आकड़ों में छात्रों के परीक्षा परिणाम, शिक्षक योग्यता, बुनियादी ढांचे की स्थिति, और अन्य शैक्षिक संसाधनों का समावेश

[1] *Author can be contacted at शिक्षा विभाग, साई नाथ विश्वविद्यालय राँची, झारखण्ड*
Received: 20-Nov-2024; Sent for Review on: 25-Nov-2024; Draft sent to Author for corrections: 12-Dec-2024; Accepted on: 16-Dec-2024; Online Available from 17-Dec-2024
DOI: 10.13140/RG.2.2.10411.30240
IJBAS-9899/© 2024 CRDEEP Journals. All Rights Reserved

किया गया है। इसके अलावा, शिक्षकों, छात्रों, और अभिभावकों के साक्षात्कार भी किए गए ताकि उनके दृष्टिकोण और अनुभवों को समझा जा सके।शिक्षाविदों ने शैक्षिक सुधारों की एक बड़ी योजना प्रस्तुत की, जिसमें से कुछ सुझावों को क्रियान्वित किया गया, जबकि कुछ सुझाव विभिन्न कारणों से लागू नहीं किए जा सके। निष्पक्ष शैक्षिक विकास और गुणवत्ता वृद्धि की दृष्टि से काफी कार्य किया गया, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए गठित आयोगों और समितियों की तार्किक और विस्तृत सिफारिशों का समुचित पालन नहीं हो सका। इसका संभावित कारण उन सुझावों की जटिलता और देश एवं समाज की आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना से जुड़ा होना था। परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में इन आयोगों और समितियों की सिफारिशों की आवश्यकता और प्रासंगिकता महसूस नहीं की गई।

राष्ट्र के समग्र विकास की व्यापक शैक्षिक प्रणाली शिक्षाविदों के समक्ष एक चुनौती बनी रही, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा का पूरा ढांचा सत्तर वर्षों के अथक प्रयासों के बावजूद आज भी अपर्याप्त और बिखरा हुआ है। पिछले सत्तर वर्षों में भारतीय शिक्षा का रास्ता कई उतार–चढ़ावों से गुजरा है और कई मोड़ों से होकर निकला है। शिक्षा क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए हैं और कई प्रवृत्तियाँ उभरी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार अन्य दशों की तुलना में तेजी से हुआ। विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी प्रयासों से शिक्षा के विस्तार में कई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, लेकिन माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सका और माध्यमिक शिक्षा का स्तर धीरे–धीरे गिरता चला गया। स्वतत्रंता प्राप्ति के बाद भारत में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार तेजी से हुआ। विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी प्रयासों से शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, लेकिन माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सका और इसका स्तर गिरता चला गया।

शोधकत्री ने प्रस्तुत शोध समस्या से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु अनके शैक्षिक साहित्यों जैसे बुच सर्वे, समसामयिक पत्र पत्रिकाएं, शोध प्रबन्ध, लघु शोध प्रबन्ध, समस्या से सम्बन्धित पुस्तकों, जनरल, ज्ञानकोष आदि का विस्तृत अध्ययन किया। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों की उपयोगिता, गुणवत्ता, महत्व आदि पर विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण शोध अध्ययन एवं निष्कर्ष समय–समय पर प्राप्त किये जाते रहे हैं। मापन उपकरणों के निर्मित हो जाने पर इस क्षेत्र में शोधों को गति एवं विस्तार प्राप्त होता है।

सम्बन्धित शोध कार्यों के उदाहरण के रूप में अग्रवाल, आर एन. (1970) ने माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के समायोजन समस्या तथा उनके व्यक्तित्व पर माता–पिता, अध्यापक तथा उनके विचारों के प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि घर, विद्यालय तथा सामाजिक क्षेत्र में छात्रों के विचारों के अनुसार अवस्था बढ़ने के साथ समायोजन की समस्या कम होती जाती है जबकि संवेगात्मक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में समायोजन की समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा, घर तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के छात्रों में समायोजन की समस्या विभिन्न प्रकार की होती है ।

वीरेश्वर, पी. (1979) ने विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन समस्या का अध्ययन किया। इसके निष्कर्षों में यह पाया गया कि बालिकाओं में समायोजन क्षमता की समस्या प्रत्येक क्षेत्र में पायी गयी। शहरी एवं ग्रामीण बालिकाओं के बीच पारिवारिक समायोजन की समस्याओं में सार्थक अन्तर पाया गया तथा शहरी एवं ग्रामीण बालिकाओं में प्राप्तांक एवं समायोजन में भी सार्थक अन्तर पाया गया। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सामाजिक समस्या पायी गयी, और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं में समायोजन के प्रति अधिक असंतोष पाया गया।

शर्मा, एस. (1982) ने माध्यमिक विद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के बौद्धिक कारकों और शैक्षिक सम्प्राप्ति का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में साहित्यिक और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिलब्धि थी। विज्ञान और वाणिज्य वर्गों के विद्यार्थी कला वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा सृजनात्मकता और बुद्धिलब्धि के क्षेत्र में अधिक उत्तम थे। विज्ञान वर्ग में अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि कम अंक प्राप्त करने वालों की अपेक्षा उत्तम थी।

वारसेनी, एम. (1984) ने किशोर बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक समायोजन और उनके व्यवहार का सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विवाहित स्त्रियोंमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति पायी गयी जबकि अविवाहित बालिकाएँ अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं पायी गयीं। अविवाहित बालिकाएँ धार्मिक, रूढ़िवादी एवं शिक्षा के आभाव एवं देश के प्रति लापरवाह पायी गयीं। विवाहित बालिकाएँ सामान्य पारिवारिक जीवन और स्वतंत्र मूल्यों के प्रति अधिक संवेदनशील थीं।

अग्रवाल, कुसुम (1986) ने छात्रों के शैक्षिक विकास पर अभिभावकों के उत्साह के स्तर का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभिभावक प्रोत्साहन और शैक्षिक विकास सकारात्मक रूप से सम्बन्धित पाये गये। शहरी उच्च समूह के छात्रों की शैक्षिक प्रगति ग्रामीण उच्च समूह के छात्रों से अधिक पायी गयी। मातृ–पितृहीन बच्चों की शैक्षिक प्रगति सार्थक रूप से उनकी अभिभावक प्रोत्साहन द्वारा प्रभावित होती है।

घलशशी, पी. जी. (1988) ने माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की अध्ययन आदत एवं कौशलों का वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि अध्ययन आदत और उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अधिकांश छात्रों को अध्ययन के उद्देश्य एवं विद्यालय के उद्देश्य के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उनका उद्देश्य अच्छी नौकरी, ज्ञान, सामाजिक स्तर आदि प्राप्त करना था। 25 प्रतिशत छात्रों को घर पर अध्ययन का अवसर नहीं मिलता था और 70 प्रतिशत से अधिक छात्र अध्ययन के लिए समय सारणी का निर्माण नहीं करते थो

मजूमदार, तारून (1988) ने कटक राज्य में माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा की स्थिति और सम्पूर्ण प्रणाली का एक अध्ययन किया। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि पश्चिम बंगाल में स्वाधीनता के बाद स्कूल शिक्षा में कई सुधार किये गये किन्तु निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। पाठ्यक्रमीय एवं संस्थागत परिवर्तन एक शून्यता एवं भ्रम की स्थिति पैदा की।

भट्ट, गनेश (1989) ने माध्यमिक शिक्षा एक प्रणाली उपागम का अध्ययन किया। इसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय की सम्पूर्ण उपलब्धता की जाँच करना था। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि कर्नाटक राज्य में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार स्थिर रूप में हुआ। यद्यपि राज्य में माध्यमिक शिक्षा का विकास हुआ किन्तु इसमें लिंग एवं सामाजिक समूह सम्बन्धी असमानताएँ तथा ग्रामीण नगरीय तथा जनपदीय विभेदनाएँ पायी गयीं।

बुधदेव, पी. एवं रवीना बी. (1989) ने विभिन्न विद्यालयी विषयों के प्रति माध्यमिक विद्यालय के बच्चों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि बालिकाओं ने बालकों की अपेक्षा गुजराती, गणित, हिन्दी, सामाजिक विषय और संस्कृत में बेहतर अभिवृत्ति दिखलायी जबकि बालकों ने विज्ञान में बालिकाओं से बेहतर अभिवृत्ति प्रदर्शित की। उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चों की अभिवृत्ति गणित और अंग्रेजी में उच्च पायी गयी जबकि निम्न बुद्धिलब्धि के छात्रों की अभिवृत्ति हिन्दी में उच्च पायी गयी।

दवे मधु एवं नन्दा पी. (1989) ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कक्षा–10 के छात्रों का विद्यालयों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण शहरी छात्रों में ग्रामीण छात्रों से अधिक पाया गया। विद्यालय के प्रति छात्रों के दृष्टिकोणों में सार्थक अन्तर पाया गया। नगरीय क्षेत्र के छात्रों का दृष्टिकोण ग्रामीण छात्रों से उच्च पाया गया। विद्यालयी कार्यक्रमों के प्रति शहरी छात्रों का दृष्टिकोण ग्रामीण छात्रों से उच्च पाया गया।

महेशन, गिरजा (1989) ने कर्नाटक की 2 स्तर की शिक्षा की कुछ समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि 2 स्तर की कक्षाओं के जुड़े होने से गुणात्मक सुधार हेतु अत्यन्त उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। हालांकि, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों पर पर्याप्त कार्य बोझ पड़ता है।

परिणाम और चर्चा

1. शिक्षक योग्यता और प्रशिक्षणरू सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की योग्यता सामान्यतः उच्च होती है, परंतु प्रशिक्षण और निरंतर विकास के अवसरों की कमी के कारण उनका प्रभाव सीमित रहता है। दूसरी ओर, निजी विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षण पद्धतियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। बुनियादी ढांचा और संसाधन निजी विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति और शैक्षिक संसाधन सरकारी विद्यालयों की तुलना में अधिक बेहतर होते हैं। इससे छात्रों को एक समृद्ध शैक्षिक वातावरण मिलता है, जो उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करता है।
3. छात्र प्रदर्शन रू परीक्षा परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि निजी विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन सरकारी विद्यालयों के छात्रों से बेहतर होता है। इसका मुख्य कारण संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षण पद्धतियों में अंतर है।
4. अभिभावक और समुदाय की भागीदारी निजी विद्यालयों में अभिभावक और समुदाय की भागीदारी अधिक होती है, जिससे छात्रों को समर्थन और प्रेरणा मिलती है। सरकारी विद्यालयों में इस भागीदारी की कमी के कारण छात्रों की प्रेरणा और प्रदर्शन प्रभावित होता है।

सारांश और सुझाव

शोध के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच की असमानताएँ झारखंड के शैक्षिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इन असमानताओं को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं

1. शिक्षक प्रशिक्षण और विकास सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, ताकि वे नवीनतम शिक्षण पद्धतियों से अवगत हो सकें और उन्हें अपनाएँ।
2. बुनियादी ढांचे का सुधार सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और शैक्षिक संसाधनों को बेहतर बनाया जाए, ताकि छात्रों को एक समद्ध शैक्षिक वातावरण मिल सके।
3. अभिभावक और समुदाय की भागीदारी सरकारी विद्यालयों में अभिभावक और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि छात्रों को समर्थन और प्रेरणा मिल सके।
4. नीतिगत सुधार रू शिक्षा विभाग द्वारा नीतिगत सुधार किए जाएँ, जिसमें सरकारी विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जाएँ और उन्हें लागू किया जाए।

इस प्रकार, यह अध्ययन उत्तराखंड के शैक्षिक परिदृश्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है और सरकारी व निजी विद्यालयों के बीच की असमानताओं को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

सन्दर्भ

1. अक्षर, जवाहिरः भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं, दिल्लीः रिसर्च पब्लिकेशन, 1956
2. अग्रवाल, जे.सी. यंग मार्क्स इन दी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, नई दिल्लीः ओकां बुक्स एंड कंपनी, 1962
3. अग्रवाल, जे.सी.ः स्वतत्रं भारत में शिक्षा का विकास, नई दिल्लीः आर्य पब्लिशिंग हाउस, 1962
4. अग्रवाल, आई.पी. रिसर्च इन एजुकेशन फील्ड्स ऑफ एजुकेशनः कंसेप्ट्स, टेड्रंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स, नई दिल्लीः स्टर्लिंग पब्लिशर्स, 1988।
5. अलग्नि, फफीयूः मनोविज्ञान और शिक्षा में साख्यिकी, आगरा–2 फोक्सोन पुस्तकालय, 1986
6. अनकोल, एल.बी. एवं मुँकु, एल.एम.ः भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, लखनऊः उत्तर प्रदेश हिंदी पुस्तक केंद्र, 1975
7. आर्य, डोनाल्ड इंटरनेशनल वॉयस ऑफ एजुकेशन, न्युयॉर्कः प्रेस एजेंसी, 1972
8. अमजर, आर.एल. एवं बर्नरव, टी.ए. स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ रिसर्च, न्यू यॉर्कः मेडिलन बुक कंपनी, 1962
9. अन, जे.डब्ल्यू.. बरदास, जे. और शार्मा, ए.बी. एजुकेशनल फॉर्म ऑफ इंडिया, वेसलेनः फिनस पब्लिकेशन, 1979
10. कपिला, एच.डी. सांख्यिकी के मलू तत्व, आगराः फोक्सोन पुस्तकालय, 1994
11. कपिल्गर, एफ. फॉर्मेशनः एक विश्लेषण, न्युयॉर्कः हॉल रीविंगटन एंड विन्सटन, 1966
12. कबीर, हुमायूं स्वतत्रं भारत में शिक्षा, दिल्लीः प्रशासन और योजना, 1967
13. कर, ए.आर. और देशमुख, ए.जी. वेस्टसे इन कॉलजे एजुकेशन, पुणेः गौकले इंस्टिट्यटू ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनॉमिक्स, 1963
14. खिगर, एम.डी. फाउंडेशन ऑफ इनडियन एजुकेशन, लखनऊः हेम हाउस, 1980